

रक्षा के लिये क्या-क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ;

कृषि तथा ग्रामीण विकास और नगरिक पुर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) आरम्भ में पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में मूल्यों में गिरावट आई। तथापि, अब मूल्य बढ़ने लगे हैं।

(ख) सरकारी एजेंसियों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ तथा प्रादेशिक सहकारी संघों ने विभिन्न राज्यों में पहले ही आलू की वसूली आरम्भ कर दी है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा प्रादेशिक सहकारी संघ ने प्रचलित मूल्यों तथा उत्पादकों में व्याप्त सुख को ध्यान में रखते हुए उन स्थानों का निर्धारण करना है जहां से सरकारी एजेंसियां आलू की खरीद करेंगी। कुल मिलाकर फर्रुखाबाद, मेरठ तथा बदायूं के क्षेत्रों से खरीद की गई है।

(घ) उत्तर प्रदेश में एकत्र किए गए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सभी खर्चें मिलाकर आलू की प्रति क्विंटल औसत उत्पादन लागत करीब 40.00 रुपए आने का अनुमान लगाया गया है। किसानों को प्राप्त होने वाली निवल आय शुरू से लेकर खुदाई का कार्य पूरे होने तक प्राप्त किए गए उत्पाद की कुल लागत पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हों, सरकार द्वारा विपणन सहायता प्रदान की जा रही है।

Guidlines to State Governments

*331. SHRI SATYA PAL MALIK:
SHRI RAMESHWAR SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Governments have not been following

the guidelines issued by the Centre regarding agricultural development and have been misleading the Centre in respect of production figures; and

(b) if so, what are the details thereof of stating the names of the States which have been misleading the Centre regarding the production figures and what is the reaction of Government with regard thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Issuance of free Rail-travel passes

*332. SHRI RAM LAKHAN PRASAD GUPTA:

SHRI LAL K. ADVANI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of free rail-travel passes issued by Government to persons other than Members of various Railway Committees during the following periods:—

(1) from March 25, 1977 to July 20, 1979;

(2) from July 21, 1979 to January 15, 1980;

(3) from January 16, 1980 to December 31, 1980; and

(4) from January 1, 1981 to January 15, 1982?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALIKARJUN): The number of complimentary card passes issued to persons other than Members of various Rail-